

मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई पंचम वरुञ्जल मंत्रिपरिषद की बैठक

खर्चाघाट नहर मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 46 करोड़ 43 लाख से अधिक की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्रि-परिषद की पंचम वरुञ्जल बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने खर्चाघाट नहर मध्यम सिंचाई परियोजना रूपांकित सिंचाई क्षमता 3500 हेक्टेयर के लिए 46 करोड़ 43 लाख 21 हजार की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत भोपाल बायपास मार्ग पर कार, हल्के (वाणिज्यिक) वाहन, बस, ट्रक, मट्टी एक्सल ट्रक पर दूरी आधारित टोल दर निर्धारित की गई है। साथ ही मासिक पास की राशि 85 रुपये निरत की गई है। सरकारी कर्तव्य पर भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन के सभी यान, संसद तथा विधानसभा के सदस्यों के यान, भारतीय सेना की ड्यूटी के सभी यान, एयूवीएस, फायर विंडोड, भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान, भूतपूर्व विधायकों एवं संसदों के यान, कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर-ट्राली, आटो रिक्शा, दो पहिया एवं



बैलगाड़ियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमानता प्राप्त पत्रकार को मार्ग पर टोल से छूट रहेगी। दीनदयाल अंबेदेकर रसोई योजना में 44 नए अतिरिक्त केंद्र खुलेंगे। मंत्रिपरिषद ने दीनदयाल अंबेदेकर रसोई योजना को कुछ संशोधनों के साथ निरंतर रखने की मजूरी दी है। योजना में पूर्व में 56 केंद्रों के अतिरिक्त 44 नए केंद्रों के साथ कुल 100 रसोई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योजनांतर्गत दिन का भोजन 10 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के परिचालन के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मांग अनुसार गेहूँ और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में औद्योगिकी नीति एवं निवेश सर्वधन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत धन राशि उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी अनुयायिक कार्यावाही के लिए नगरीय

विकास एवं आवास विभाग को अधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद ने आवास निर्भर भारत अभियान के पैकेज 2 में भारत सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत प्रारंभ की गई अप्रोडेंडल रेंटल हाउसिंग स्काम को प्रवेश में लागू करने की मजूरी दी। योजना 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू की जायेगी। आवासन ग्राहकडॉरिन के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा मेमॉरैंडम ऑफ एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अधिकृत किया है। योजना स्थल पर ट्रंक अंधोसरचना का कार्य निकाय द्वारा किया जायेगा। इन कार्यों का वित्तीय भार निकायों पर आवेगा। ट्रंक अंधोसरचना को पूरा करने के लिए राज्य शासन की ओर से प्रति परिवारियोजना 5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा में 50 प्रतिशत का वित्तीय अनुदान अलग से दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 68 हजार हितग्राही लाभान्वित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रोटी, कपड़ा और मकान सुलभ आवश्यकता है। अपना स्वयं का मकान हो, यह हर व्यक्ति का सपना होता है। इसे पूरा करने के लिये राज्य शासन प्राण-प्राण से जुटा है। हमारे जिन भाई-बहनों के पास मकान नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए सहायता दी जा रही है। यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा आज प्रधानमंत्री आवास योजना के 68 हजार हितग्राहियों के खातों में चौबीस और अंतिम किस्त के 102 करोड़ रूपए सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित किए गए। मंत्रालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में अब तक 20 लाख 30 हजार से से 17

लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वर्ष 2019-20 में 6 लाख आवास का लक्ष्य था, जिसमें से 3 लाख 45 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं। जिन भाई-बहनों को अब तक आवास नहीं मिले है, वे निराश न हों। उन्हें भी सिंगल क्लिक से अंतरित हुए 102 करोड़ रूपए, अक्सर और आनंद के साथ करें गृह प्रवेश: मुख्यमंत्री

आवास प्लस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण का कार्य पूरा हो गया है उनके गृह प्रवेश का कार्यक्रम 12 सितम्बर को आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भोपाल से वे स्वयं कार्यक्रम से जुड़ेंगे।

सभी ग्राम पंचायतों में यह कार्यक्रम उसका के रूप में मनाया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संदेश 12 सितम्बर को अपराह्न 11 बजे प्रसारित होगा। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों से इस संवेधान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मेरा लक्ष्य है कि सभी गरीबों का कल्याण हो, उन्हें सभी सुविधाएँ मिलें। इस दिशा में केंद्र और राज्य शासन लगातार सक्रिय है। आगामी 16 सितम्बर को प्रदेश के 37 लाख लोगों को यशस्वितरण की शुरुआत की जाएगी। इसी क्रम में 18 सितम्बर को फसल बीमा योजना के 4 हजार 600 करोड़ रूपए किसानों के खातों में डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राशि अंतरण के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से बातचीत की।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान निरंतर चले: मुख्यमंत्री



डोर-टू-डोर सैणल लेने का कार्य नहीं होगा, फीवर रलीकन में सैणल लेने की व्यवस्था होगी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद बैठक के पूर्व कोविड-19 की मध्यप्रदेश में स्ट्रेटर को जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अन्य स्थानों से रोगी भोपाल और अन्य बड़े नगरों में उपचार के लिए आ रहे हैं। ये रोगी अपना उपचार विला स्तर पर ही करना सकते हैं। प्रत्येक जिले में उपचार उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सर्वजन के संख्या को निरंतर दिए कि किसी भी बच्चा। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में कंट्रोल कमांड केंद्र सक्रिय हों। यहां डॉक्टर भी परामर्श देने के लिए उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि किसी भी अस्पताल में अक्सिजीन का अभाव न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता में तो प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में लाई जा रही अक्सिजीन का भी उपचार में प्राथमिकता से उपयोग होगा चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आम जन दारा मास्क के उपयोग की अनिवार्यता भी सुनिश्चित हो। इसके लिए भी अभियान चलता रहे (मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नगरीय प्रशासन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रचार कार्य करें। जागरूकता के प्रयास बढ़ें। बसों में यात्री अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, यह परिवहन विभाग सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अलार्क के बाद जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अन्य स्थानों से रोगी भोपाल और अन्य बड़े नगरों में उपचार के लिए आ रहे हैं। ये रोगी अपना उपचार विला स्तर पर ही करना सकते हैं। प्रत्येक जिले में उपचार उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि किसी भी बच्चा। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में कंट्रोल कमांड केंद्र सक्रिय हों। यहां डॉक्टर भी परामर्श देने के लिए उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि किसी भी अस्पताल में अक्सिजीन का अभाव न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता में तो प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में लाई जा रही अक्सिजीन का भी उपचार में प्राथमिकता से उपयोग होगा चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आम जन दारा मास्क के उपयोग की अनिवार्यता भी सुनिश्चित हो। इसके लिए भी अभियान चलता रहे (मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नगरीय प्रशासन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रचार कार्य करें। जागरूकता के प्रयास बढ़ें। बसों में यात्री

आऊट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से इन्वोवेशन प्रारंभ होता है- यशोधरा

भोपाल। संघर्ष विश्व में कोविड महामारी के कारण बन जीवन असमान हो गया है इस संकट काल में खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा रावे सिंधिया चुनौती को अवसर में बदलने और खेल के क्षेत्र में निरत नयाचार को प्रारंभ कर क्रियान्वित करने में प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को श्रीमती सिंधिया ने लगभग दो घंटे अतिरिक्त ओलंपिक, पैरा ओलंपिक एथ्लेटिज्म के वाइस प्रेसिडेंट श्री कैली स्कौनर के साथ % प्रोग्राम के लाइव ऑनलाइन सेशन में चर्चा की। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि कोविड-19 संकल्पन के कारण विश्व भर में खेल गतिविधियां बंद थीं। अंदरूनी अर्थव्यवस्था के बाद डिजिटल को प्रशिक्षण का निर्वाहण कार्यक्रम शुरू से शुरू किया गया है। अब डिजिटल और प्रशिक्षण पोर्टल हार्ड परफार्मेंस लीडरशिप प्रोग्राम की

बताया। क्रिस्वीर इन्वोवेशन में आईडिया जर्नल, प्राल्म सांख्यिक और इन्फॉर्मेटियन शामिल हैं श्री कैली ने केटीए, श्री, रनिंग के उद्धारण के साथ बताया कि कैसे खेलों में इन्वोवेशन का उपयोग कर हाई परफार्मेंस ओलंपिक में अचीव किया जा सकता है। उन्होंने अपने सेशन में टेलेंट आइडेंटिफिकेशन तथा टेलेंट ट्रांसफर में अमेरिका में किए गए इन्वोवेशन को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक टेलेंट स्काउटिंग कैम्प के लिए एक डेयार किया था, वह इतना इम्पार्सिंग था कि उसको देखकर नौ हजार से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस टेलेंट स्काउटिंग कैम्प में स्क्रॉनिंग कराई। इसी तरह उन्होंने अमेरिका के विभिन्न खेल खेलों से अपने ऐसे खिलाड़ियों को चिन्हित करने को कहा जो उनके खेल में अपने सफल नहीं हुए, जिन्हा उनमें टेलेंट था।

समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करें: मंत्री कंधाना

भोपाल। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री ऐदल सिंह कंधाना ने दतेहरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का कार्य समय-समय में और गुणवत्ता के साथ किए जाने के निर्देश पीएचईड अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि समय-सीमा में कार्य पूर्ण किए जाने से जहाँ आम जनता को योजना का लाभ मिल जाता है वहीं निर्धारित लागत में कार्य होने से सरकार के धन की बचत भी होती है मुद्दा जिले के कौतवाल 'डैम (जल स्रोत) से 22 ग्रामों में शरूट नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराने की इस योजना का लागत 32.24 करोड़ रूपये है। दतेहरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना से 45 हजार से अधिक आबादी को 7 हजार 460 शरूट नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। योजना का कार्य प्राप्ति पर है और इसे पूर्ण करने का लक्ष्य 31 मार्च 2021 निर्धारित किया गया है। योजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों में मिर्जान, दीधावाली, दतेहरा, परीक्षा, कृपारपुर, अजनीदा, सुजापुर, खेरिया कला, काजी बसवाड़ा, नागर, कोलवाल, खिलेला, बमरौली, मदन बसवा, गिरगोण, विस्तौली, बरेंदा, खैरा, नरसिंहपुर, माता बसवाड़ा, भिकौलाकापुर एवं भातपुर शामिल हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमलीकरण में विश्वविद्यालय मार्गदर्शन करें

भोपाल। राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्याल पर सफलता पूर्वक लाने के लिए विभिन्न पहलुओं के अमलीकरण में शासकीय और निजी विश्वविद्यालय मार्ग दर्शक की भूमिका में आगे आये। विश्वविद्यालय राजवार परक शिक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम निर्माण, शोधों को प्रयोग शाला से व्यवहारिकता की जमीन पर लाने, रीक्षणिक गुणवत्ता, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर को शिक्षा पद्धति, इन्टरनिंग, क्रेडिट स्कोर, शिक्षक प्रशिक्षण जैसे विभिन्न पहलुओं पर विषयवार समूह बनाकर चिंतन मनन करें। श्रीमती पटेल आज राजवहन में शासकीय विश्वविद्यालयों की अकादमिक गतिविधियों की समीक्षा के दौरान विधायी कांफ्रेंस में भाग लीं



राज्यपाल पटेल ने कुलपतियों की विडियों कांफ्रेंस में दिए निर्देश

को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उच्चशिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बरकतउल्ला एवं देवी अहिल्या शासकीय

विश्व विद्यालयों के कुलपति मौजूद थे। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने क्षेत्र ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के पहले 5 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नीति की सफलता का आधार है। इसमें भी आगन्वाड़ी के पहले 3 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आगन्वाड़ी में सिगुर के लालन-पालन

की पद्धति और प्रणाली कैसी हो कि बच्चे सुनकर, लिखने से खेल कर सीख सकें। अनुशासन, सम्मान, स्वच्छता, करुणा, सेवा, खेह और भातुल के संस्कार उनमें बस जाए। इसी तरह प्राथमिक शिक्षा में कक्षा, प्रसंग, विषयों का निर्धारण और शिक्षक प्रशिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं में दिशा दर्शन जरूरी है। माध्यमिक स्तर पर इंटर्निंग जैसी व्यवस्था किस तरह क्रियान्वित की जाये। उसका स्वरूप कैसे निर्धारित किया जाए ऐसे अनेक आध्यात्म पर विचार विमर्श सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। क्रियान्वयन की ररेरखा पर व्यापक स्तर पर विश्वविद्यालय परिसंवाद करें। जहाँ भी जो भी अच्छे है, उसे प्रार कर एकीकृत करें। क्रियान्वयन पथ को आलोचित करें। श्रीमती पटेल ने कहा कि उच्चशिक्षा के

क्षेत्र में नवाचारी सोच की रीति नीति के साथ कार्य किया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय उसकी विशेषता के आधार पर नीति के आध्यात्म को चिन्हित करें। क्रियान्वयन कार्य का स्वरूप और खावा तैयार करें। औद्योगिक क्षेत्रों के विश्वविद्यालय राजवार परक शिक्षा के शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण और अनुसंधान कर पाठ्यक्रमों का बचन और निर्माण करें। इसी तरह अन्य विश्वविद्यालय भी विशेषता क्षेत्र का निर्माण कर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर पहलू और आध्यात्म के सफल क्रियान्वयन को कार्य योजना बनाएं। उन्ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वैचारिक की श्रृंखला चलाने वाले को जरूरत बताएँ। शिक्षकों को एक वर्ष में अनिवार्य पाठ्यक्रम स्वयं का कोई एक कोर्स करने के निर्देश दिए।

